to work on commeracial basis, expected to earn some profit, provide something, and then help HAL and purchase it from them, that kind ot stand cannot be taken. As at present we will have to consider the difficulty of Yayudoot, difficulties ot HAL and consider how best we can use the capacity produced in the country. That is the totality of the view of this problem we are taking as a Government.

SHRI KAMAL MORARKA : Sir, I want to know trom the Minister what is the total amount that Vayudoot has *been* allowed to spend to acquire these aircraft, especially because there is no budgetary support. Are they allowed to borrow money trom Air-India, Indian Airliness and the financial institutions without limit? Is there any limit laid down? Especially because — I want to draw your attention to this—Vayudoot has not published accounts ever since its inception. There are no accounts. Mr. Suresh Kalmadi has been kind enough to tell us that they owe 15 crores TO (his man and 10 crores to that man. But Vayudoot has not given us the accounts. These have not been placed on the Table of the House. It is a scandalous situation. I want a clarification trom the Minister on this.

SHRI SHIVRAJ PATIL : Sir, this is being unkind to Vayudoot, which is a child trying to grow up and meet the demands and requirements.

I have been saying that you have not given them sufficient budgetary support. They are taking loans trom different organisations. The Finance Ministry has issued directions saying that public sector undertakings in one Ministry should help each other in financial matters. Air-India and Indian Airlines have been good enough to give some money to them ta meet certain ot the requirements. And the loan that is given by the Indian airlines and Air-India is not sufficient to *meet* all the requirements, they are trying to earn money and they are trying to meet the requirements which are expanding like anything. Vayudoot is going to a hundred and one places, let us understand, with 24 aircratt and to areas where nobody is going. These are some of the difficulties. We are expecting a service trom Vayudoot which is as good as Indian Airlines, give.

MR. CHAIRMAN: What about the accounts?

SHRI SHIVRAJ PATIL: As tar as accounts are concerned, there are certain things which have to be done. Now there are certain assets which have *to* be assessed *by* some other organisation also and when that is done, accounts will be given. But that does not mean that we do not have the accounts with the Vayudoot. We can account to the Parliament but it should come as a totality and not in piecemeal. That is the difficulty.

SHRI MURASOLI MARAN : How many years will it take?

MR. CHAIRMAN : Question No. 24.

मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय सहायता

***24. श्री अजीत जोगी :†**
श्री चन्दन शर्मा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में विभिन्न विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय सरकार द्वारा विश्वविद्यालय-वार कितनी-कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ;

---

† सभा में यह प्रश्न श्री अजीत जोगी द्वारा पूछा गया ।

(ख) क्या उपरोक्त विश्वविद्यालयों को प्रदान की जा रही सहायता को अपर्याप्त पाया गया है और उनके द्वारा और अधिक सहायता की मांग की गई है, और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० साही): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों को आयोग द्वारा अनुमोदित और जारी किए गए अनुदानों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। [देखिये परिशिष्ट 151, अनुपत्र सं० 1]

(ख) और (ग) आयोग के अनुसार विश्वविद्यालयों के प्रस्ताव, सातवीं योजना के लिए विश्वविद्यालयों के विकास प्रस्तावों के वास्ते विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के आधार पर तैयार किए गए थे और आवंटनों को प्रत्येक विश्वविद्यालय के कुलपति और विषय-विशेषज्ञ के साथ परामर्श/विचार विमर्श के बाद अनुमोदित किया गया था। अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के प्रश्न पर आवंटित निधियों को पूरी तरह उपयोग में लाए जाने के बाद ही विचार किया जा सकता है।

श्री अजीत जोगी : मान्यवर, जो उत्तर मंत्री महोदय ने दिया है, उसको पढ़ कर बड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे विश्वविद्यालय हैं, जो मध्य प्रदेश में हैं। उनका नाम ही नहीं है, जैसे बिलासपुर में गुरु घासी दास विश्वविद्यालय 1983 से चल रहा है। उसके नाम का उल्लेख ही नहीं है।

तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह उत्तर पूर्ण है, और यदि नहीं तो ऐसे कितने विश्वविद्यालय हैं जो इसमें से छूट गये हैं ?

दूसरी बात मैं यह भी जानना चाहुंगा कि इस पंच वर्षीय योजना में आपने 1435 करोड़ रुपये देने का लक्ष्य मध्य प्रदेश के लिए निर्धारित किया था। अब सातवीं पंच वर्षीय योजना लगभग खत्म हो रही है, केवल 850 करोड़ रुपये दिये हैं, छः सौ करोड़ और देने शेष हैं। इतनी बड़ी राशि जो शेष रह गई है, वह मध्य प्रदेश जैसे बड़े प्रांत के लिए अत्यावश्यक है। क्या उसे सातवीं पंच वर्षीय योजना में आप पूरा दे देंगे ?

श्री एल. पी. साही : मान्यवर, गुरु घासी दास विश्वविद्यालय 1983 में स्थापित हुआ, यह बात सही है.... **(व्यवधान)**

श्री अजीत जोगी : पर वह छूट कैसे गया ?

श्री एल० पी० साही : लेकिन वह विश्व-विद्यालय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा जो गाइडलाइन्स बनाये गये थे, वह पूरा नहीं करता था। इसलिए उसकी छानबीन चल रही थी। इसीलिए उसका नाम इसमें नहीं दिया गया है।

श्री अजीत जोगी : छह साल से छानबीन ही चल रही है।

श्री एल० पी० साही : छानबीन का मतलब है कि विश्वविद्यालय का रेकोग्निशन तभी होता है जब वह इन्फ्रा-स्ट्रक्चरल फैसि-लिटीज पूरा कर लेता है। देखना पड़ता है कि इसमें कितने विद्यार्थी हैं, कितने शिक्षक हैं, वहां कितने विषय पढ़ाये जाते हैं और जैसे लाइब्रेरी में किताबें है कि नहीं, इक्विपमेंट है कि नहीं, क्वार्टर्ज हैं कि नहीं इत्यादि। यह सब जो इन्फ्रा-स्ट्रक्चरल फैसिलिटीज है, यह उनको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। जो स्टार्ट करते हैं–राज्य सरकार करे, केन्द्र सरकार करे या कोई ट्रस्ट करे, जो भी कोई करे, उसको यह मान्यतायें पूरी करनी पड़ती हैं। उसके बाद ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उसको अपनी लिस्ट में लेता है।

इसलिए यहां पर उन्हीं विश्वविद्यालयों का नाम दिया गया है, जो विश्वविद्यालय पहले से स्वीकृत हैं।

श्री सभापति : प्रश्न पूछा गया है कि बाकी के लिए कब तक आप दे देंगे।

श्री एल० पी० साही : जहां तक दूसरे प्रश्न का सवाल है...

श्री अजीत जोगी : बाकी के लिए कब तक दे देंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिवशंकर : अब आपने पूछ लिया है। हम कर देंगे।

श्री एल० पी० साही : 1435.93 करोड़ दे चुके हैं, जो 59 परसेंट हुआ।

श्री सभापति : बाकी भी जल्दी दे देंगे ?

श्री एल० पी० साही : बाकी खर्च करने पर निर्भर करता है।

श्री सभापति : खर्च करने पर दे देंगे।

श्री एल० पी० साही : जैसे-जैसे खर्च करेंगे, वैसे-वैसे हम देते जाने को तैयार हैं।

MR. CHAIRMAN : Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Allocation of funds for Sanibalpur-Talcher Rail Line Project

* 25. SHRI BASUDEV MOHAPATRA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) what amount of fund has "been allocated tor Sambalpur-Tal-chei Rail Line Project in 1988-89 and 1989-90;

(b) what amount has been spent sc tar on the project;

(c) that is the total length of the Line completed so far in kilometres; and

(d) by when the whole project is. likely to be ready ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) —

1958-89	1989-90
Rs. fl crores	Rs. 10 crores

(b) Rs. 15- 48 crores (upto May, 1989).

(c) and (d) Construction works are in progress on 42 km from Tal-cher end and 43 km trom SambalpUr end. Completion of whole project will depend on the availability of resources in coming years.

Indo-Nepal Talks

*26. SHRIMATI VEENA VERMA : SHRI PARVATHANENI UPENDRA:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the outcome of the latest exchange of letters between the Foreign Ministers of India and Nepal;

(b) whether Nepal has proposed to have the most favoured nation treatment in regard to trade and commerce; and

(c) if so, what is the response of the Government of India thereto and whether there are any prospects of a negotiated settlement of the impasse between the two countries ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI K. NATWAR SINGH): (a) In the letter of June 16, 1989, from Shri P.V. Narasimha Rao, Minister of External Affairs to Shri Shailendra Kumar Upa-dhyay, the Honourable Minister of Foreign Affairs of his Majesty's Government of Nepal, a comprehensive agenda covering all relevant aspects of Indo-Nepal relations had been proposed. In his response of June 26, 1989, the Honourable Minister of Foreign Affairs of Nepal has proposed certain amendments to this agenda. These are now being examined.

(b) In their draft for a new Indo-Nepal Trade Treaty handed over-